>

Title: Need for vacation of stay granted by the High Court in regard to issuance of new list of B.P.L. in Uttar Pradesh.

श्री मुंशी राम (बिजनौर) : सभापति जी, देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को भारत सरकार हजारों-करोड़ो रुपये का अनुदान देती है। जिस गरीब के लिए भारत सरकार वह अनुदान देती है, उस गरीब तक अनुदान का अधिकांश अंश अधिकारियों और चंद लोगों की जेब में चला जाता है। इसका उदाहरण भारत सरकार के तमाम सर्वे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी सदन में स्वीकार किया है कि यह 40 प्रतिशत तक ही लिंकेज है। ...(व्यवधान) सर, मुझे अपनी बात तो कहने दीजिए। ये सर्वे इसके सीधा-सीधा उदाहरण हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीपीएल की जो नयी सूची तैयार की गयी थी, उस पर ऐसे कारोबार करने वाले लोगों ने उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश से रोक लगवा दी है। मेरी इस सदन के माध्यम से भारत सरकार और प्रदेश सरकार से मांग है कि उच्च न्यायालय ने नयी बीपीएल की सूची जारी करने के लिए जो रोक लगायी है, उसे उच्चतम न्यायालय से निरस्त कराया जाये, जिससे जो गरीब लोग, बीपीएल की सूची में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार हैं, उनको उसका हक मिल सके।

सभापति महोदय, मेरा एक अनुरोध और था। यह एक बहुत ही गरीब परिवार का मसला है। ...(व्यवधान) मेरे लोकसभा क्षेत्र का निवासी श्री रोहतास सिंह ...(व्यवधान)